Title: Need to conduct CBI inquirty into the alleged financial irregularities in Khadi and Village Industry Commission.

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार का ध्यान नागपुर शाखा द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग में 1.25 करोड़ रुपये से अधिक के सब्सिडी घोटाले के पर्दाफाश की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। केन्द्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रशिक्षित बेरोजगार युवकों को आत्मनिर्भर बनाने एवं सुदृढ़ ग्राम स्वराज्य की भावना के तहत बैंकों के माध्यम से 25 लाख रुपये तक का ऋण देने का तय हुआ था एवं उक्त ऋण पर 4.5 लाख रुपये की सब्सिडी उपलब्ध कराने की योजना शुरू की थी। परंतु खादी ग्रामोद्योग के अधिकारियों ने गैरपात्र लोगों के साथ मिलीभगत करके न केवल उन्हे बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया, बल्कि सरकारी सब्सिडी भी दिलवाई। खादी एवं ग्रामोद्योग के अधिकारियों की कृपा से रोजगार गारंटी योजना के लिए मिले धन से भंडारा व नागपुर के 5 व्यापारियों ने राइस मिलें खड़ी कर लीं।

सी.बी.आई. के छापे में ऐसे 52 मामले सामने आए हैं, जिनमें खादी और ग्रामोद्योग के अधिकारियों ने गैरपात्र लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि दिखाई है। सी.बी.आई. की देशव्यापी कार्रवाई की शुरूआत खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नागपुर कार्यालय में हुई है।

यह अत्यंत गम्भीर मामला है। इसलिए इस पर सरकार को शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए और देखना चाहिए कि गैरपात्र लोगों को सरकारी धन क्यों और कैसे दिया गया? केन्द्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रशिक्षित बेरोजगार युवकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो धन दिया था, उसका दुरुपयोग जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया है, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए, जिससे भविष्य में इस प्रकार का भ्रष्टाचार न होने पाये।